P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-12* August- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश का योगदान : भारत के संदर्भ में एक वाणिज्यिक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Contribution of Foreign Direct Investment in Banking Sector: A Commercial Analytical Study in The Context of India

Paper Submission: 15/08/2020, Date of Acceptance: 26/08/2020, Date of Publication: 27/08/2020

दीपक कुमार
छात्र,
वाणिज्य विभाग,
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, भारत

सारांश

किसी भी राष्ट्र के विकास में विदेशी पूँजी निवेश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कभी–कभी राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होते है तो विदेशी पूँजी निवेश ही राष्ट्रीय बचत को पूरा करती है। आजादी के पूर्व भारतवर्ष में बैंकिंग क्षेत्र का स्वरूप पूरी तरह से पूँजीवादी था तथा व्यापारिक बैंक मुख्य रूप सें व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं हितों की पूर्ति करते थे। आजादी के बाद से लेकर आज तक भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में अनेक उतार–चढ़ाव आए हैं। देश में रूवतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कार्यरत बैंकिंग तंत्र का फैलाव बैंकिंग तंत्र का विभिन्न ग्राम्य क्षेत्रों तक नहीं था, परंतु बाद में बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना से भारतीय बैंकिंग सेवाओं को देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाया, इसके अतिरिक्त साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ने भी इस कार्य में विशिष्ट योगदान किया है । केन्द्र सरकार ने समय–समय पर इसे आगे बढ़ाने के जिए अनेक कदम उठाए है जैसे– नाबार्ड की स्थापना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, लीड बैंक योजना आदि मोटे तौर पर वित्तीय समावेशन की दिशा में उठाये गये कदम आदि है ।

Foreign capital investment has much importance in the development of any Nation. Sometime, resources are not enough for the complete development of the nation in this condition foreign capital investment fulfills the National Savings. Before independence the concept of banking was totally based on capitalism and commercial banks Mainly fulfilled the Desires and needs of traders and industrial areas. Since Independence and till now many ups and downs occurred in banking areas. When the country got independence, expansion of working banking system was not in different rural areas but later by the nationalization of banks and by the establishment of Bhartiya State bank, banking services was expanded in India rural areas. Besides this, the establishment of Gramin Bank has contributed much in this area. The central government takes essential steps on time to time to expand it. Like- the establishment of NABARD, imagery service sector, primary received areas, Lead Bank Plant were important steps taken in the area of financial inclusion.

मुख्य शब्द : पूँजी, निवेश, संसाधन, व्यावसायिक।
Capital, Investment, Resources, Occupational.

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के विकास में विदेशी पूँजी निवेश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कभी–कभी राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होते है तो विदेशी पूँजी निवेश ही राष्ट्रीय बचत को पूरा करती है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति, 1948 से ही विदेशी पूँजी निवेश को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया। साथ ही देश में विकास क्षेत्रों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण हेतु व्यापारिक, विभिन्न कृषि एवं औद्योगिक नीतियों की संरचना समय–समय पर की गई। लेकिन 50 प्रतिशत से कम की हिस्सेदारी विदेशी पूँजी का नियत्रंण भारतीय हाथों में रखे जाने की दृष्टि से प्रबंधन एवं स्वामित्व किया गया है।

वर्ष 1980–90 तक इस विचारधारा को सभी औद्योगिक नीतियों में सम्बल मिला है। लेकिन सन् 1990 के बाद पूँजी की उपलब्धता प्राप्त करने, विदेशी ऋणों का भार में वृद्धि हेतु, तकनीकी अंतर को अंतरराष्ट्रीय स्तर कम करना, प्रतिस्पर्धा का सामना करने, निर्यात बाजार को खोलना, मानवीय व प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने तथा आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने खुली एवं उदार क्रांतिकारी वर्ष 1991 में औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ की। 1991 की औद्योगिक नीति में विदेशी फर्मों को, विशेषकर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, दूरसंचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक मदों आदि में प्रत्यक्ष निवेश की छूट दी गई। जिसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत की ओर आकर्षित हुआ।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत आलेख के निम्न उद्देश्य है–

1. देश के बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश का अध्ययन करना।
2. देश के बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश के योगदान का पता लगाना।

अध्ययन विधि

अध्ययन की विधि विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक है। इस अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन सामग्री की प्राप्ति शोधग्रन्थों, संदर्भ ग्रन्थों एवं प्रतिष्ठित लेखकों की पुस्तकों, आलेखों से की गई है तथा तथ्यों का विवेचन प्रामणिक ढंग से किया गया है।

साहित्यावलोकन

जैन ममता एवं मिनल लोधाना (2012) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों आमंत्रित करने के लिए खुदरा क्षेत्र का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में सुधारों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण किया है। इसी क्रम में बाबर एस० एन० और बी० वी० खेदारे (2012) ने भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की संरचना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभों का अध्ययन किया है। इसके बाद त्रिवेदी, चक्रपाणि एवं दुबे, गिरीश मोहन (2019) ने ''भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति'' प्रस्तुत आलेख में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अर्थ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवाह मार्ग, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निर्धारक तत्व को विस्तार से बताया है।

बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश का योगदान

आजादी के बाद से लेकर आज तक भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में अनेक उतार–चढ़ाव आए हैं। आजादी के पूर्व भारतवर्ष में बैंकिंग क्षेत्र का स्वरूप पूरी तरह से पूँजीवादी था तथा व्यापारिक बैंक मुख्य रूप सें व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं हितों की पूर्ति करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यापारिक बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति में जब कोई परिवर्तन नहीं आया। सामाजिक बैंकिंग की दिशा में व्यापारिक बैंकों ने उदासीन रवैया होने के कारण केन्द्र सरकार ने 19 जुलाई, 1969 में देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे बैंकों की ऋण नीतियों तथा कार्यप्रणाली बहुत बड़ा बदलाव आया है। 1950 के बाद भारत सरकार की अप्रैल 1948 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में औद्योगिकीकरण के लिए विदेशी पूँजी की उपयोगिता को स्वीकार किया। तात्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने 6 अप्रैल 1949 को भारत के संसद भवन में भाषण देते हुए विदशी पूँजी निवेशकों को आश्वासन दिए तथा सरकार की नीति को स्पष्ट किये। आन्तरिक बचत में अन्तर को घाटने के लिए तथा देश की न्यूनतम पूँजी आवश्यकताओं पर सन् 1949–50 में प्रशुल्क आयोग ने जोर दिया। देश में आजादी के बाद कार्यरत बैंकिंग तंत्र का फैलाव बैंकिंग तंत्र का विभिन्न ग्राम्य क्षेत्रों तक नहीं था, परंतु बाद में बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना से भारतीय बैंकिंग सेवाओं को देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाया, इसके अतिरिक्त साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ने भी इस कार्य में विशिष्ट योगदान किया है।

केन्द्र सरकार ने समय–समय पर इसे आगे बढ़ाने के जिए अनेक कदम उठाए है जैसे– नाबार्ड की स्थापना, सेवा क्षेत्र कल्पना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, लीड बैंक योजना आदि मोटे तौर पर वित्तीय समावेशन की दिशा में उठाये गये कदम ही थे।

एम0 नरसिंहम की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 14 अगस्त, 1991 को सार्वजनिक व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की असफलताओं को ध्यान में रखकर एक समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट 20 नवंबर, 1991 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि देश की कार्यप्रणाली एवं वित्तीय प्रणाली की संरचना में सुधार करने की आवश्यकता है तथा साथ ही यह भी व्यक्त किया गया व्यापारिक बैंकों की गिरती लाभदायकता के लिए सार्वजनिक दायित्वों से बंधे होने, ब्याज का गिरती आय, निरंतर बैंकों की बढ़ती परिचालन लागत को उत्तरदायी माना, बैंकिंग प्रणाली में प्रशासनिक हस्तक्षेप व राजनीतिक को भी बैंकों की घटती लाभदायकता के लिए दोषी माना है।

सन् 1991 से पहले भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग प्रतिबन्धित था। 1991 में औद्योगिक नीति लाने का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार का विदेशी निवेश को प्रत्याहित करना था। इस नीति में विदेशी पूँजी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% कर दी गई एवं गैर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो में भी विदेशी पूँजी निवेश को अधिक सरल बनाया। वर्ष 1993 में ''फेरा'' को विदेशी मुद्रा नियमन कानून बनाया गया। हाल के वर्षों में लगभग क्षेत्रों में विदेशी निवेश को निर्धारित सीमाओं के भीतर कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पर्णू छूट प्रदान किया गया है। कुछ क्षेत्रों में तो विदेशी निवेश की अनुमति शत–प्रतिशत है।

1991 के पूर्व देश में बैंकिंग नीतियाँ पूर्ण रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियन्त्रित होती थी। आर्थिक उदारीकरण के पहले भारतीय बैंकिंग क्षेत्र प्रणाली में प्रतियोगिता का अभाव था, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा हेतु बैंक अपनी ब्याज दर का निर्धारण करने में भी स्वतंत्र नहीं थे। 1990 में नये बैंकों के प्रवेश हेतु नीतियों को उदार बनाया गया। इससे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हुई। 1994 से 2000 की समयावधि में देश में 20 विदेशी बैंकों तथा 7 निजी बैंकों में कार्य प्रारम्भ किया। वर्ष 2004

में विदेशी बैंकों व निजी बैंकों सम्मिलित हिस्सेदारी कुल बैंकिंग क्षेत्र की 20% थी।

देश के इस सामाजिक मिशन में निजी व विदेशी बैंकों ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में वर्ष 2000 के बाद अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। इस अवधि में नीतियों और नियमों में जो परिवर्तन किए गए, उनके कारण परिसम्पत्ति, बैंकों के विकास, गुणवत्ता और लाभप्रदता में काफी सुधार हुआ है। भारतीय बैंक अब अपने क्षेत्र के दूसरे बैंकों के मुकाबले में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। अप्रैल 2001, में बैंकिंग सूचकांक प्रकाशित आंकड़े में 51% वार्षिक की दर से बढ़ रहा है जबकि बाजार विकास का सूचकांक इस अवधि में 27% तक सीमित रहा है।

2001 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए पूँजी के मुकाबले में जोखिमयुक्त परिसंपत्तियों का अनुपात 11.4% से बढ़कर मार्च 2010 में 13.6% हो गया था जो कि बेसल फ्रेमवर्क के अनुसार निर्धारित 8% से और भारतीय बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए मानक 9% से भी अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 फरवरी 2002 को बैकिंग क्षेत्र में सीधे विदेशी पूँजीनिवेश के सदंर्भ में एक मुख्य नीति परिवर्तन की घोषणा की। इसमें सभी स्रोतों से 49% तक सीधा पूँजीनिवशे निजी क्षेत्र के बैंकों में लागू हो सकेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये 20% सीधा विदेशी पूँजीनिवेश और पोर्टफोलियो पूँजीनिवेश चालू रहेगा। निजी बैंकिंग के क्षेत्र वर्तमान समय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बैंक की कुल चुकता पूँजी का 74% तक कर दी गयी है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इसकी सीमा 20% है।

देश में विदेशी पूँजी के आगमन में वृद्धि करने के साथ–साथ बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करना तथा बैंकिंग प्रणाली में नवीन तकनीक और उन्नत प्रबन्धन को बढ़ावा देना भी है। इसका एक उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना भी है। कुछ लोगों का मानना है कि बैंक क्षेत्र में वित्त पूँजी की मजबूती और विदशी पूँजी के बढ़ते असर का हमारे राष्ट्र की प्रभुसत्ता के लिये, जनता की रोजी–रोटी व खुशहाली के लिये भयानक अंजाम होगा। वही भारतीय रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण नियामक, पर्यवक्षेकीय और सावधानी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसके परिणामस्वरूप भारतीय बैंक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय संकट से अछूते रहे और संकट का उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

निष्कर्ष

बैंकों के स्वामित्व में सरकारी अंश में कमी सार्वजनिक क्षेत्र के कारण सभंव हुआ है। क्योंकि निजीकरण को छोड़कर सुधारों के उपाय अत्यंत सफल रहे हैं। हाल के वर्षों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आवटंनीय, तकनीकी और लागत दक्षता निजी और विदेशी बैंकों की तुलना में कहीं अधिक रही है। 2009 में भारत सरकार और आरबीआई द्वारा' वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति' रिपोर्ट में भारत के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक आकलन करते हुए बताया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों ने स्वस्थ विकास दर दर्शाया है और उनके कामकाज में सुधार हुआ है, जो कि परिसंपत्ति की गुणवत्ता, पूँजी की पर्याप्तता, आमदनी और दक्षता संकेतकों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *एगोसिन, एम0 एण्ड आर0 मेयर (2000), फारेन इनवेस्टमेंट इन डेवलपिंग कन्ट्रीज : डज इट क्राउड इन डोमिस्टिक इनवेस्टमेटं , डिस्कशन पेपर नं0 146, अंकटाड, जिनेवा.*
2. *सिन्हा, वी0सी0 (2003), ''अन्तराष्ट्रीय अर्थशास्त्र'' मयूर पेपरबैक्स, नोएडा.*
3. *उपाध्याय, शर्मा, दयाल (2004), ''व्यावसायिक वातावरण'', रमेश बुक डिपो, जयपुर.*
4. *कुलश्रेष्ठ, आर0एस0 (2005), ''वित्तीय प्रबंध'', साहित्य भवन पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि आगरा.*
5. *मिश्र एवं पुरी (2008), ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई.*
6. *शर्मा, रविश कुमार (2010) भारतीय अर्थ व्यवस्था में विदेशी पूँजी निवेश की भूमिका, इंटरनेशनल रिफर्ड रिसर्च जर्नल, वा0–2, इश्यू–15, अप्रैल 2010, पृ0 86–89.*
7. *जायसवाल, गापेाल (2010), वित्तीय सुधारों में बैंकिंग, योजना, फरवरी 2010, पृ0 31*
8. *सोनी, सपना (2011) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सेवा क्षेत्र का विकास, योजना, प्रकाशन विभाग, योजना भवन, नई दिल्ली, सितंबर 2011*
9. *सविता, जी0 (2013), द रोल ऑफ एफ.डी.आई. इन इण्डियन बैंकिंग सेक्टर : कन्ट्री वाइज एनालिसिस, ए.एस.एम.एस इण्टरनेशनल ई–जर्नल ऑफ आनगोइंग रिसर्च इन मैनेजमेंट एण्ड आई0टी0.*